



Neutral Citation No. - 2026: AHC:6327

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 42118 सन् 2025

समद

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता

:- अंकित अग्रवाल, दिलीप कुमार पटेल

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

श्री अंकित अग्रवाल, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री पुनीत कुमार सिंह, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत आवेदन आवेदक समद की ओर से विचारण की लम्बितता के दौरान उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3(1) के अन्तर्गत थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 618 of 2025 में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे किसी अन्य उद्देश्य से इस प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। 02 प्रकरणों आपराधिक पूर्ववृत्त की पर्याप्त व्याख्या की गई है।

यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में उल्लिखित किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है तथा उसने किसी गिरोह की गतिविधियों को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न तो दुष्प्रेरित किया है और न ही सहायता की है। आवेदक का उक्त प्रकरण के अतिरिक्त कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया से भागने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। आवेदक 06.07.2025 से कारागार में है। न्यायालय में भारी लम्बितता के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान अ.शा.अ. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है, तथापि आवेदक के विरुद्ध विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रदर्शित मामलों के अतिरिक्त कोई अन्य मामला नहीं दर्शाया।

तथ्यों की समग्रता, अभिलेख से प्रतिबिम्बित प्रकृति एवं साक्ष्य पर विचार करते हुए तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मुझे यह जमानत के योग्य प्रकरण लगता है। अतः यह जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक **समद** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत मुचलका एवं दो विश्वसनीय जमानतदारों, जो समान राशि के होंगे, प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रेरणा, धमकी या वचन देकर उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विरत करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/डर नहीं डालेगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) प्रकरण का उद्घाटन, (ii) आरोप-विरचन, तथा (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अन्तर्गत बयान अंकन हेतु नियत तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजनार्थ सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से प्रकरण के गुण-दोष पर मत का प्रकटन नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर पूर्णतः स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए स्वतंत्र है।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

09 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश